साप्ताहिक

जागत गांव हमार

पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक

RNI-MPHIN/2015/72544

चौपाल से भोपाल तक

भोपाल, सोमवार, 16-22 दिसंबर 2024 वर्ष-10, अंक-35

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना, रीवा, शिवपुरी से एक साथ प्रकाशित

पृष्ठः-8,मूल्यः- 2 रुपए

सीएम ने जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर के विद्यार्थियों से किया संवाद

बड़ी उपलब्धि! विश्व की पहली नदी जोड़ो परियोजनाओं से लाभान्वित होगा मध्यप्रदेश

- केन-बेतवा और पार्वती-कालीसिंध-चंबल का ग्वालियर को मिलेगा लाभ
- भारत की नक्षत्र आधारित काल गणना की विधि सर्वाधिक सटीक
- नवीन शिक्षा नीति से होगा विद्यार्थियों का सम्पूर्ण व्यक्तित्व विकास

भोपाल। जागत गांव हमार

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विश्व की पहली नदी जोड़ो परियोजना आकार लेने जा रही है। यह उनके द्वारा देश को दी गई एक बड़ी सौगात है, सौभाग्य है कि इससे मध्यप्रदेश लाभान्वित होगा और ग्वालियर अंचल को एक नहीं दो-दो परियोजनाओं का लाभ मिलेगा। केन-बेतवा लिंक परियोजना का अनुमानित बजट एक लाख करोड़ रुपए है। इसके साथ ही पार्वती-काली-सिंध-चंबल लिंक परियोजना का भी क्रियान्वयन आरंभ हो रहा है। शिवपुरी एक मात्र ऐसा जिला होगा, जो इन दोनों महत्वाकांक्षी परियोजनाओं से लाभान्वित होगा। प्रधानमंत्री मोदी के इस आशीर्वाद से आने वाली पीढ़ी मध्यप्रदेश की प्रगति और उन्नति का एक नया इतिहास रचेगी और मध्यप्रदेश एक आदर्श राज्य के रूप में आकार लेगा। इससे बुंदेलखण्ड क्षेत्र के साढ़े आठ लाख निवासी लाभान्वित होंगे। लॉर्ड मैकाले द्वारा लागू शिक्षा व्यवस्था के परिणाम स्वरूप विद्यार्थियों का सम्पूर्ण मनोविकास बाधित रहा। नई शिक्षा नीति ने ज्ञानार्जन की जिज्ञासा का समाधान करते हुए छात्र-छात्राओं के सम्पूर्ण व्यक्तित्व विकास के अवसर प्रदान किए हैं। विद्यार्थियों में जिज्ञासा के भाव को बनाए रखने और उन्हें विभिन्न क्षेत्रों की नवीनतम जानकारियां उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ही युवा संवाद कार्यक्रम आरंभ किया गया है। मुख्यमंत्री ग्वालियर में जीवाजी विश्वविद्यालय के युवा संवाद कार्यक्रम में विद्यार्थियों से चर्चा कर रहे थे।

काल गणना का केंद्र है उज्जैन

मुख्यमंत्री ने कहा कि विज्ञान की दुनिया के एक अनूठे संग्रहालय का शुभारंभ हुआ है, ग्वालियर के लिए आज का दिन विशेष है। सिंधिया राज्य की दूसरी राजधानी उज्जैन काल की गणना का केंद्र रहा है। विश्व में समय की गणना को सूर्य या चंद्रमा से जोड़ा गया है। जबकि भारत में काल की गणना का आधार नक्षत्र रहे हैं। यह समय की सूक्ष्मतम और सर्वाधिक सटीक गणना है। इस परम्परा के आधार पर ही पंचांग हमें सूर्यग्रहण, चंद्रग्रहण और अन्य खगोलीय घटनाओं की स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराते हैं। सनातन संस्कृति की इस विधा के परिणाम स्वरूप ही देश का जन-जन समय की गणना को सरलतापूर्वक समझने में सक्षम हो पाया।

युवा विश्व का भविष्यः सिंधिया

केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि युवा प्रदेश और देश ही नहीं, विश्व का भविष्य हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव युवाओं के साथ संवाद ही नहीं, प्रदेश के एक-एक अंचल का निर्माण कर रहे हैं। उनके अंदर मध्यप्रदेश को अग्रणी बनाने की कशिश और जज्बा है। उन्होंने युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिये विभिन्न योजनाएं, औद्योगिकीकरण विकास के लिए कॉन्क्लेव और इंटरप्रेन्योरशिप के लिये स्टार्टपेड की व्यवस्था की है। हमारे मध्यप्रदेश का वैभव, भविष्य और शिल्पकार यह युवा पीढ़ी ही रहेगी। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मध्यप्रदेश के युवा देश, प्रदेश और विश्व का निर्माण करने में अपनी सर्वश्रेष्ठ भूमिका निभाएंगे।

पूरी दुनिया भारत को देखेगीः तोमर

विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री ग्वालियर की पावन धरा पर युवाओं से संवाद करने आए हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। उन्होंने कहा कि हम सब जानते हैं कि कोई भी संस्था हो, कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी राज्य हो या कोई भी देश हो उसका भविष्य नौनिहाल बच्चे ही हुआ करते हैं। आजादी के जब 100 वर्ष पूरे होंगे और आज का भारत विकसित भारत के रूप में पूरी दुनिया देखेगी, उस समय आज की पीढ़ी साक्षी बनेगी। प्रधानमंत्री मोदी का प्रयास है कि भारत विश्व में विकसित राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने आये। इस दिशा में सभी को साथ चलने की जरूरत है और सभी को अपना योगदान देने की जरूरत है। विधानसभा अध्यक्ष ने महारानी लक्ष्मीबाई, सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को याद करते हुए कहा कि आजादी के युद्धों में हमारे अधिकांश महान योद्धा भी युवा अवस्था में थे, जिन्होंने भारत माता के पैरों में पड़ी हुई परतंत्रता की बेड़ियों को काटने के लिए अपने प्राणों को न्योछावर किया।

पंजाब और अन्य राज्यों में मटर की फसल खराब

देश भर की मंडी में इस बार उतरेगी मालवा की मटर

भोपाल। जागत गांव हमार

स्ट्राबेरी, अनार, वीएनआर अमरूद, रेड डायमंड अमरूद, सोयाबीन, गेहूं आदि के लिए मालवा प्रसिद्ध है। यहां के मटर देश के हर कोने में सबको भा रही है। मौसम की अनुकूलता के कारण इस बार मटर की क्वालिटी बेहद खास है। यही कारण है कि पहली बार एक माह से मटर के भाव एक समान मिल रहे हैं, जिससे किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। दरअसल, पंजाब के अमृतसर में इस साल मटर की फसल कोहरे के कारण खराब हो गई है। राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश में मटर जनवरी के अंतिम सप्ताह तक आने की उम्मीद है। माना जा रहा है अगले दो महीनों तक मालवा के मटर का दबदबा चहुंओर रहेगा।

सोना ने दिया दगा

80 के दशक से दबदबा रखने वाला पीला सोना यानी सोयाबीन पिछले कुछ वर्षों से किसानों को दगा दे रहा है। इस साल भी इसके कम दाम और कम उत्पादन ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेरा है, इसलिए किसानों की सारी उम्मीद मटर की फसल पर टिकी थी। कृषकों ने सोयाबीन के तुरंत बाद मटर की बोवनी कर दी थी, लेकिन मानसून की आखिरी वर्षा ने मटर की फसल को बर्बाद कर दिया। जब दोबारा बोवनी की नौबत आई, तो मंहगे बीज और पहली बोवनी वर्षा में धुलने के कारण कई किसानों ने इससे तौबा कर ली।

रकबा घटा, डिमांड बढ़ी

साल 2023-24 में मटर का रकबा 16 हजार 500 हेक्टेयर था, जो इस वर्ष घटकर करीब साढ़े आठ से नौ हजार हेक्टेयर के करीब ही रह गया। इससे इसकी डिमांड चहुंओर से निकलकर सामने आ रही है। बाद में बोई गई मटर की फसल को मौसम का अच्छा साथ मिला। इस बार पैदावार भी बंपर हो रही है तथा गुणवत्ता भी काफी सुधार दिखाई दिया है।

कई राज्यों में मालवा के मटर की खपत

महाराष्ट्र से केंद्र शासित प्रदेश तक खपत मालवा के मटर की खपत महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली समेत केंद्र शासित प्रदेश दमन तक में हो रही है। यहां की महाराष्ट्र में मुंबई व पुणे तथा गुजरात में पोरबंदर, राजकोट, अहमदाबाद, भावनगर, जामनगर, सूरत, वापी तथा राजस्थान में जयपुर आदि शहरों के साथ केंद्र शासित प्रदेश दमन तक भेजी जा रही है। दिल्ली से भी मटर की डिमांड आ रही है, किंतु वहां की दूरी अधिक होने पर 24 घंटे का समय लग रहा है, जिससे मटर की क्वालिटी प्रभावित होने से दाम नहीं मिल रहे हैं। यदि दिल्ली-मुंबई एट लेन पूरा हो जाता है, तब दिल्ली की राह आसान हो जाएगी।

भारतनेट परियोजना में ब्रांडबैंड से जुड़ेगी प्रदेश की हर ग्राम पंचायत

भोपाल। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा द्वारा लोकसभा में पूछे गए प्रश्न के जवाब में जानकारी दि गई है कि प्रदेश की ग्राम पंचायतों को भारतनेट परियोजना के अंतर्गत ब्राडबैंड से कनेक्ट किया जा रहा है। इस परियोजना के अंतर्गत पन्ना, कटनी और छतरपुर जिलों की अधिकांश ग्राम पंचायतों को ब्राडबैंड से कनेक्ट किया जा चुका है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में बताया गया कि अक्टूबर, 2024 तक मध्यप्रदेश की 17,850 ग्राम पंचायतों को ब्राडबैंड से जोड़ा जा चुका है। पन्ना जिले की 395 ग्राम पंचायतों में से 390 को, कटनी जिले की 407 ग्राम पंचायतों में से 115 को एवं छतरपुर जिले की 558 ग्राम पंचायतों में से 225 को ब्राडबैंड सेवा से जोड़ा जा चुका है।

-हर पंचायत को सुशासन की इकाई बनाना चाहते हैं पीएम मोदी

-आरबीआई ने खोला राहत का पिटारा..अब कुछ भी गिरवी रखने की नहीं होगी जरूरत

किसानों को एक जनवरी से मिलेगा दो लाख का कर्ज

भोपाल। जागत गांव हमार

किसानों की वित्तीय जरूरत पूरी करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने कौलैटरल फ्री लोन की रकम को बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया है। बढ़ोत्तरी का यह फैसला 1 जनवरी 2025 से लागू कर दिया जाएगा। खास बात यह है कि इसके तहत किसानों को कुछ भी गिरवी रखे बिना 2 लाख मिल सकेंगे और सबसे कम ब्याज दर चुकानी होगी। इस फैसले से किसान क्रेडिट कार्ड धारकों की संख्या में भी इजाफा देखने को मिलेगा। बैंकों को इस संबंध में किसानों को जागरूक करने के लिए व्यापक स्तर पर अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। यह कदम छोटे और सीमांत किसानों को बढ़ती लागत के बीच सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से उठाया गया है। नए निर्देश में देशभर के बैंकों को प्रति उधारकर्ता दो लाख तक के कृषि और इससे जुड़ी गतिविधियों के लिए लोन के लिए जमानत और मार्जिन आवश्यकताओं को माफ करने का निर्देश दिया गया है।

छोटे और सीमांत किसानों को फायदा

कृषि मंत्रालय के अनुसार यह निर्णय बढ़ती लागत और किसानों के लिए ऋण सुलभता में सुधार की आवश्यकता के जवाब में लिया गया है। बयान में कहा गया है कि इस उपाय से छोटे और सीमांत भूमिधारक 86 प्रतिशत से अधिक किसानों को काफी लाभ होगा। बैंकों को दिशा-निर्देशों को तेजी से लागू करने और नए ऋण प्रावधानों के बारे में व्यापक जागरूकता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।

किसान क्रेडिट कार्ड से मिलेगा लोन

आरबीआई के इस फैसले से केसीसी लोन तक आसान पहुंच की सुविधा मिलने की उम्मीद है। यह सरकार की संशोधित ब्याज सहायता योजना का पूरक होगा, जो 4 प्रतिशत प्रभावी ब्याज दर पर 3 लाख तक का लोन देती है। इस पहल को कृषि क्षेत्र में वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक कदम के रूप में देखा जा रहा है, जिससे किसानों को कृषि कार्यों में निवेश करने और अपनी आजीविका में सुधार करने के लिए बहुत जरूरी वित्तीय लचीलापन मिलेगा।

देश का हृदय प्रदेश अपने वन, जल, अन्न, खनिज, कला, संस्कृति और परंपराओं की समृद्धि के लिए प्रसिद्ध है अपना मध्यप्रदेश। पुण्य सलिला मां नर्मदा और भगवान श्रीमहाकालेश्वर की पावन छाया अनगिनत बलिदानियों और महापुरुषों की कर्मभूमि एवं तपोभूमि रहा हमारा प्रदेश ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और धार्मिक रूप से समृद्ध है। आज, मध्यप्रदेश अपने सांस्कृतिक वैभव को संरक्षित करते हुए विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत के संकल्प के तहत, प्रदेश के गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी के सशक्तिकरण पर आधारित चार मुख्य स्तंभों पर कार्य कर रहा है। यह बता सीएम डॉ. मोहन यादव ने मध्यप्रदेश सरकार के एक वर्ष पूर्ण होने पर भोपाल में संवाददाताओं से चर्चा के दौरान कही।

मोहनराज का एक साल: मध्यप्रदेश में एक लाख से अधिक दीदीयां बनी लखपति

» 1450 किमी लंबे श्रीराम वन गमन पथ निर्माण का निर्णय लिया गया

» हर नगरीय निकाय में गीता भवन के निर्माण का निर्णय लिया गया

» हर ग्रापं में पीएम किसान समृद्धि केंद्र की स्थापना होगी

किसान, गाय-गरीब का कल्याण

प्रदेश में बहेगी दूध की गंगा

लगातार अग्रणी मध्यप्रदेश

पीएम स्व-निधि योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, पीएम आवास योजना, कृषि अवसंरचना निधि, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, स्वामित्व योजना, नशामुक्त भारत अभियान, आयुष्मान भारत योजना, मछुआ क्रेडिट कार्ड योजना, राष्ट्रीय पशु रोगनियंत्रण कार्यक्रम, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, राष्ट्रीय आजीविका मिशन और स्वच्छ भारत मिशन में मध्यप्रदेश लगातार अग्रणी है।

निर्माणाधीन महालोक

निर्माणाधीन महाकाल महालोक उज्जैन, संत रविदास लोक सागर, माँ नर्मदा महालोक अमरकंटक, देवी अहिल्या लोक खरगोन, नागलवाड़ी लोक बड़वानी, देवी लोक सलकनपुर, श्री रामराजा लोक ओरछा, जाम सांवली श्री हनुमान लोक-पांढुर्णा, श्री पशुपतिनाथ लोक मंदसौर, श्री परशुराम लोक जानापाव, महाराणा प्रताप लोक भोपाल, भादवामाता लोक नीमच, माँ पीताम्बरा लोक दतिया और माता मंदिर लोक रतनगढ़ को पूरा किया जाएगा।

भोपाल। प्रधान संपादक

सीएम ने कहा कि प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए नवाचारी पहल करते हुए रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव और रोड शो के माध्यम से हर क्षेत्र के औद्योगिक विकास को बल दिया जा रहा है। राज्य सरकार के प्रतिबद्ध प्रयासों का ही यह सुखद परिणाम है कि नए निवेश प्रस्तावों से मध्यप्रदेश का औद्योगिक परिदृश्य सुदृढ़ होने और नए रोजगार के अवसर सृजित होने की राहें खुल रही हैं। सांस्कृतिक पुनर्जागरण के क्रम में श्रीराम वन गमन पथ, श्रीकृष्ण पाथेय और विक्रम संवत की पुनर्स्थापना जैसे अनेक प्रयास हमारी ऐतिहासिक धरोहर को नई ऊर्जा दे रहे हैं। यह समय आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रगति का है। मध्यप्रदेश की साढ़े आठ करोड़ जनता के सहयोग और संकल्प से हम आत्मनिर्भर प्रदेश का निर्माण करके विकसित भारत के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए कृत संकल्पित हैं। प्रदेश में मुख्यमंत्री जनकल्याण अभियान और राज्य सरकार के एक वर्ष पूर्ण होने पर जनकल्याण पर्व शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री जनकल्याण अभियान में शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं से वंचित नागरिकों को लाभान्वित करने और जन समस्याओं का मौके पर शिविर लगाकर निराकरण किया जाएगा। इसमें केन्द्र और राज्य सरकार की शत-प्रतिशत सैचुरेशन की चिन्हित-34 हितग्राही मूलक योजनाओं में और 11 लक्ष्य आधारित योजनाओं के साथ विभिन्न विभागों से संबंधित 63 सेवाएं शिविर लगाकर आमजन को लाभान्वित किया जाएगा। जन-कल्याण पर्व में विभिन्न विभागों की गतिविधियां, विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि-पूजन के साथ जन-कल्याण के कार्य प्रमुखता से किये जायेंगे होंगे। इन कार्यक्रमों में आमजन की सहभागिता भी सुनिश्चित की जाएगी।

रोजगार से संवरेगा मप्र

-वर्ष 2025 को औद्योगिक वर्ष के रूप में किया गया घोषित। अब तक सम्पन्न हुईं 6 रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा और नर्मदापुरम से रु. 2.07 लाख करोड़, मुंबई, बेंगलुरू, कोयम्बटूर, कोलकाता में किए गए रोड-शो कार्यक्रमों में रु. 1 लाख करोड़ से अधिक के निवेश, भोपाल में आयोजित खनन कॉन्क्लेव में रुपये 20 हजार करोड़ के निवेश और यूके और जर्मनी की यात्रा में रु. 78 हजार करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन संयुक्त प्रयासों से कुल चार लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए है। इनसे तीन लाख से अधिक रोजगार सृजन होगा। प्रदेश के हर जिले में निवेश प्रोत्साहन केन्द्र प्रारंभ किए गए।

गरीब कल्याण

» संबल 2.0 के अंतर्गत 1 करोड़ 73 लाख श्रमिकों का पंजीयन। 40 हजार से अधिक श्रमिक परिवारों को 895 करोड़ से अधिक की अनुग्रह राशि का अंतरण।

» सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में प्रतिमाह 55 लाख हितग्राहियों को 3 हजार करोड़ रुपए से अधिक राशि का अंतरण।

» प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में 36 लाख से अधिक परिवारों और प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में 8 लाख से अधिक परिवारों का साकार हुआ घर का सपना।

» स्वामित्व योजना में 24 लाख लोगों को भू-अधिकार पत्र वितरित कर मध्यप्रदेश देश में प्रथम बना।

» वोकल फॉर लोकल के तहत धनतेरस से देवउठनी ग्यारस तक शिल्पकार और छोटे व्यवसायियों को कर से मुक्त रखा।

» पीएम स्वनिधि योजना में 11 लाख से अधिक हितग्राहियों को 10 से 50 हजार रुपए तक के ऋण सहायता उपलब्ध कराई गई।

युवाओं पर फोकस

» प्रदेश के विश्वविद्यालयों के कुलपति अब कुलगुरु कहलाएंगे।

» राज्य स्तरीय रोजगार दिवस के अवसर पर रिकॉर्ड 7 लाख युवाओं को 5 हजार करोड़ रुपए का स्व-रोजगार ऋण वितरित हुआ।

» सभी शासकीय विभागों में लगभग 1 लाख पदों पर भर्तियां की जा रही। आगामी 5 वर्ष में 2.50 लाख सरकारी नौकरियां उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।

» गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के उद्देश्य से 55 जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस प्रारंभ।

» विश्वविद्यालयों में छात्र-छात्राओं की अंकसूची एवं उपाधियों को डीजी लॉकर में अपलोड करने की व्यवस्था लागू की गई।

किसान कल्याण

» प्रत्येक ग्राम पंचायत में पीएम किसान समृद्धि केंद्र की स्थापना होगी।

» रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना में किसानों को 1 हजार प्रति क्विंटल की दर से अधिकतम 3900 रुपए प्रति हेक्टेयर की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी।

» किसानों को समर्थन मूल्य पर उपार्जित गेहूं पर प्रति क्विंटल 125 रुपए बोनस का भुगतान।

» सोयाबीन का समर्थन मूल्य 4,892 रुपए प्रति क्विंटल की दर से उपार्जन करने का निर्णय लिया।

» मुख्यमंत्री किसान कल्याण सम्मान निधि में 6 हजार रूपये प्रति वर्ष का भुगतान सीधे किसानों के खातों में किया जा रहा है।

» फसल की बोनी के सही आंकलन के लिए डिजिटल क्राप योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

» राजस्व महाअभियान के दो चरणों में 80 लाख से अधिक लंबित प्रकरणों का निपटारा किया गया। राजस्व महाअभियान 3.0 शुरू हुआ।

समृद्ध हो रही संस्कृति

» श्रीकृष्ण लीलाओं से जुड़े सभी तीर्थ स्थलों (सांदीपनि आश्रम, नारायणा गांव उज्जैन, जानापाव इंदौर एवं अमझेरा धार) को जोड़ कर श्रीकृष्ण पाथेय का होगा निर्माण, श्रीकृष्ण पाथेय न्यास के गठन को स्वीकृति दी गई।

» विक्रमोत्सव के अवसर पर विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का शुभारंभ कर भारतीय काल गणना परंपरा का साक्षात्कार पूरी दुनिया से कराया गया।

» 1450 किमी लंबे श्रीराम वन गमन पथ निर्माण का निर्णय लिया गया।

» प्रत्येक नगरीय निकाय में गीता भवन के निर्माण का निर्णय लिया गया।

» गीता जयंती पर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया गया है।

संकल्प-पत्र की पूर्ति

प्रदेश की उन्नति और प्रगति के साथ जनता को खुशहाल बनाने के लिए हमारी सरकार का जो संकल्प-पत्र था, उसपर चरणबद्ध तरीके से तेजी से कार्य हो रहा है। प्रदेश के विकास और जनता के हित में तय किये गये 456 संकल्पों में एक साल के अंदर 45 संकल्प पूरे किए जा चुके हैं और 268 संकल्पों पर तेजी से कार्य चल रहा है। आगे आने वाले 4 वर्ष में हम एक-एक संकल्प पूरा करेंगे। इंदौर के हुकुमचंद मिल के 4 हजार 800 श्रमिक परिवारों की लंबित राशि 224 करोड़ का भुगतान किया गया।

मोहन यादव सरकार

काम लगातार-फैसले असरदार

कानून-व्यवस्था

-वारंट और समन की तामील के लिए ई-तकनीक का उपयोग किया जाएगा। मध्यप्रदेश ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य। सायबर डेस्क स्थापित करने का निर्णय।

-विशेष पिछड़ी जनजाति के युवाओं को सेना, अर्धसैनिक बलों और पुलिस सेवाओं में भर्ती के लिए प्रशिक्षण के लिए जनजातीय बटालियन गठित करने का निर्णय।

-पुलिस में स्पोर्ट्स कोटा निर्धारित, प्रतिवर्ष 10 सब इंस्पेक्टर एवं 50 कॉन्स्टेबल की नियुक्ति होगी।

सिंचाई का बढ़ता रकबा

-1320 करोड़ की लागत की वितरंगी डाबयुक्त सूक्ष्म सिंचाई परियोजना को स्वीकृति। सिंगरौली जिले में परियोजना से 32 हजार 125 हेक्टेयर में सिंचाई क्षेत्र विकसित होगा।

-4 हजार 197 करोड़ 58 लाख रुपए की लागत से जावद-नीमच डाबयुक्त सूक्ष्म सिंचाई परियोजना को स्वीकृति।

किसानों को सौर ऊर्जा

» एक लाख 25 हजार अस्थाई विद्युत कनेक्शन लेने वाले कृषकों को सौर ऊर्जा के पम्प प्रदाय किए जाएंगे। अगले चार वर्ष में सौर ऊर्जा पम्प प्रदाय कर किसानों को विद्युत आपूर्ति में आत्मनिर्भर बनाया जाएगा।

» कृषि फसलों के विविधिकरण की पहल की जाएगी, जिससे किसानों की आय में बढ़ोत्तरी हो। अधिक दाम प्रदान करने वाली फसलों की ओर किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

» प्रदेश में वर्तमान में 50 लाख हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र है। अगले पांच वर्षों में इसे दोगुना (1 करोड़ हेक्टेयर) किया जाएगा।

» वर्तमान में 17 शासकीय मेडिकल कॉलेज है। 13 प्रायवेट मेडिकल कॉलेज है। पीपीपी मोड पर 12 और 8 शासकीय मेडिकल कॉलेज चालू किए जाएंगे।

» प्रदेश में दुग्ध समितियों का विस्तार किया जाएगा। वर्तमान में प्राथमिक दुग्ध समितियां 8,500 गांवों में ही है। एक वर्ष में 15 हजार गांवों तथा 4 वर्षों में प्रदेश के समस्त गांवों तक दुग्ध समितियां गठित की जाएंगी।

» महिला स्व-सहायता समूह को जन आंदोलन बनाया जाएगा। वर्तमान में 25 लाख महिलाएं स्व-सहायता समूह से जुड़ी है। यह संख्या चार वर्ष में 50 लाख तक बढ़ाई जाएगी।

» यात्रियों की सुविधा के लिए पूरे प्रदेश में बसों के लिये परिवहन कंपनी बनाकर संचालन किया जाएगा।

» वर्ष-2025 को उद्योग एवं रोजगार-वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। जिसमें युवाओं को शासकीय नौकरी के साथ स्व-रोजगार से जोड़ने का वृहद स्तर पर कार्य होगा। एक लाख सरकारी भर्तियां की जाएंगी।

» प्रदेश में मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र (महानगर) का गठन किया जाएगा। इंदौर-उज्जैन-देवास-धार को मिलाकर एक तथा भोपाल-सीहोर रायसेन विदिशा-ब्यावरा को मिलाकर दूसरा मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र बनाया जाएगा।

» जिला/विकासखंड/ तहसीलों/ अनुविभागों का पुनर्गठन किया जाएगा।

» केंद्र के विजन के अनुरूप राज्य के सभी संभाग मुख्यालयों जैसे ग्वालियर, सागर, रीवा, जबलपुर, नर्मदापुरम्, शहडोल आदि को भी क्षेत्रीय आर्थिक विकास केंद्र के रूप में विकसित करने की अवधारणा के साथ कार्ययोजना बनाई जाएगी।

» प्रदेश में संतुलित नगरीय विकास को गति देने तथा आर्थिक विकास के केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए पुनर्घनत्विकरण तथा पुनर्विकास नीति के अतिरिक्त एकीकृत टाउनशिप नीति तैयार की जाएगी जिसमें निजी भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा।

» प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 अंतर्गत प्रदेश के शहरी गरीब परिवार जो प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रथम चरण अंतर्गत किसी कारणवश लाभ प्राप्त नहीं कर पाये ऐसे सभी शहरी गरीब तथा मध्यम आय वर्ग के हितग्राहियों को आवास प्रदान किए जाएंगे।

» खाली मिलों जैसे हुकुमचंद/ श्री/ विनोद मिल एवं अन्य शहरों में खाली पड़ी शासकीय भूमियों पर शहरी प्रोजेक्ट लान्च किए जाएंगे।

» श्रीराम-वन-पथ-गमन तथा श्रीकृष्ण पाथेय का निर्माण किया जाएगा।

» 10 दुधारू पशु पालने पर अनुदान तथा दुग्ध उत्पादन पर बोनस दिया जाएगा।

» हरिद्वार की तर्ज पर उज्जैन का विकास किया जाएगा।

» जीवनदायिनी नर्मदा को निर्मल जल प्रवाहमान रखने के लिए कार्ययोजना बनाकर अमल में लाया जाएगा।

» कान्ह-गंभीर की तर्ज पर नदी जोड़ो परियोजनाएं स्वीकृत की जाएंगी।

» प्रदेश की सभी गौ-शालाओं का सुचारू संचालन किया जाएगा।

» जल संवर्धन अभियान और जनकल्याण अभियान प्रतिवर्ष आयोजित किए जाएंगे।

» प्रदेश में 4 मिशन (युवा, नारी, किसान और गरीब कल्याण) 26 जनवरी से प्रारंभ किए जाएंगे।

» प्रदेश में वर्तमान में कुल विद्युत उपलब्ध क्षमता 23 हजार 30 मेगावाट है। आगामी 5 वर्षों में कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 31 हजार मेगावाट करने का लक्ष्य है।

» अशोकनगर के चंदेरी के प्राणपुर ग्राम में 7 करोड़ की लागत से देश के पहले क्राफ्ट हैण्डलूम टूरिज्म विलेज का शुभारंभ।

आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं

» चिकित्सा शिक्षा विभाग और लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का विलय सुशासन और कार्यदक्षता का उदाहरण बना।

» आमजन को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने 30 मेडिकल कॉलेज का संचालन। पीपीपी मोड पर 12 शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय जल्द प्रारंभ होंगे।

» उज्जैन को मिली मध्यप्रदेश की पहली मेडिसिटी एवं शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय की सौगात।

» पीएमश्री एयर एम्बुलेंस सेवा के जरिए प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों से गंभीर रूप से बीमार/दुर्घटनाग्रस्त लोगों को एयरलिफ्ट उपलब्ध कराने के लिए सरकार की संवेदनशील पहल की गई।

» आयुष्मान भारत योजना में अब तक 4 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड वितरित कर मध्यप्रदेश देश में सबसे आगे। 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को भी आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलना शुरू।

» स्वास्थ्य संस्थानों में 46 हजार 491 नये पदों (नियमित/संविदा/आउटसोर्स) के सृजन की स्वीकृति।

सिंहस्थ मेला क्षेत्र नगर विकास

» सिंहस्थ-2028 की तैयार प्रारंभ, टास्क फोर्स का गठन हुआ।

» संकल्प पत्र 2023 उज्जैन को ग्लोबल रिपिरियुअल सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा।

» सिंहस्थ 2028 में सम्पूर्ण मेला क्षेत्र का उज्जैन विकास प्राधिकरण के माध्यम से नगर विकास योजना। अन्तर्गत स्थाई अधोसंरचना का निर्माण किया जाएगा।

» सिंहस्थ मेले के दौरान आने वाले अखाड़ों/आश्रमों/श्रद्धालुओं की स्थाई संरचना के माध्यम से आवश्यकताओं की पूर्ति की जाएगी।

» साधु-संतों के लिए हरिद्वार की तरह उज्जैन में स्थायी धार्मिक नगरी एवं आश्रम बनाए जाएंगे।

» मां-शिप्रा शुद्धिकरण का संकल्प पूरा करने के लिए 599 करोड़ की लागत से बनने वाली कान्ह वलोज डवट परियोजना का काम शुरू हुआ। सिंहस्थ में श्रद्धालु शिप्रा के जल से ही स्नान करेंगे।

» उज्जैन में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बड़े पैमाने पर शिप्रा नदी के दोनों ओर घाट निर्माण, शहर के चारों ओर सड़क परियोजनाओं में काम शुरू किया गया है।

गौ-संरक्षण-संवर्धन

» साल 2024 को गौवंश रक्षा वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है।

» दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए मध्यप्रदेश सरकार और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बीच एमओयू हुआ।

» 10 से ज्यादा गाय पालने पर सरकार द्वारा अनुदान देने का निर्णय।

» गौ-वंश के लिए बेहतर आहार हेतु प्रति गौ-वंश मिलने वाली 20 रुपए की राशि बढ़ाकर 40 रुपए करने का निर्णय।

» प्रत्येक 50 किमी पर घायल गायों के इलाज के लिए लाइव्लिक कैटल लिफ्टिंग वाहन का प्रबंध।

टाइगर रिजर्व में बढ़ोत्तरी

» मध्यप्रदेश टाइगर और चीता स्टेट के बाद बना लेपर्ड स्टेट। भारत सरकार की रिपोर्ट अनुसार प्रदेश में -3 हजार 907 तेंदुए हैं, जो कि देश में सबसे अधिक हैं।

» भोपाल का रातापानी बना प्रदेश का आठवां टाइगर रिजर्व।

» मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश और राजस्थान को मिलाकर बनेगा देश का सबसे बड़ा चीता कॉरिडोर।

» माधव नेशनल पार्क भी शीघ्र टाइगर रिजर्व घोषित होगा।

अधोसंरचना विकास

» 18 हजार 36 करोड़ की लागत से इंदौर-मनमाड़ रेलवे लाइन परियोजना को स्वीकृति, 309 किमी लंबी रेल लाइन पर 30 नए रेलवे स्टेशन बनेंगे।

» प्रदेश के जनजातीय बहुल आकांक्षी जिला बड़वानी, धार, खंडवा, खरगोन, इंदौर सहित निकटवर्ती जिले लाभान्वित होंगे।

» भारत सरकार द्वारा प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के निर्माण और सुदृढ़ीकरण के लिए 3 हजार 500 करोड़ की राशि स्वीकृत।

» मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 8,565 ग्राम 19,378 किलोमीटर लंबी सड़कों से बारहमासी मार्ग से जुड़े।

» 14440 करोड़ रुपए की लागत से भोपाल एवं इंदौर में मेट्रो रेल निर्माणाधीन।

» विंध्य क्षेत्र को मिली बड़ी सौगात। मप्र का छठा एयरपोर्ट, रीवा एयरपोर्ट का शुभारंभ।

» ग्वालियर में देश में सबसे कम समय में बनकर तैयार हुए, मध्यप्रदेश के सबसे बड़े राजमाता विजयाराजे सिंधिया एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ।

कृषि विज्ञान केंद्र के कर्मियों के भविष्य पर संकट के बादल

» डॉ. सत्येंद्र पाल सिंह, प्रमुख वैज्ञानिक - कृषि विज्ञान केंद्र, लहार (भिंड) मप्र

सम्पूर्ण देश में कृषि विज्ञान केंद्रों को कार्य करते हुए 50 वर्षों से अधिक का समय हो चुका है। जिला स्तर पर किसानों की सेवा में तत्पर एवं अपने काम की बदौलत कृषि विज्ञान केंद्र एक ऐसा नाम बन चुका है कि हर संस्था एवं विभागों की निर्भरता इन केंद्रों पर हमेशा बनी रहती है। बावजूद इसके कृषि विज्ञान केंद्र कर्मियों के वेतन, भत्तों एवं सेवा शर्तों में असंवैधानिक ढंग से कटौती कर इन्हें बंधुआ मजदूर से भी बदतर स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है।

एक पत्र के बाद कृषि विज्ञान केंद्र के कर्मियों का भविष्य अधर में लटक गया है। आखिरकार यह निर्णय किन परिस्थितियों में और क्यों लिया गया इसका जवाब देने को कोई भी संबंधित संस्था तैयार नहीं है। इस पत्र की प्राप्ति के बाद, बात अब बहुत आगे निकल चुकी है। परिणाम स्वरुप पूरे देश में कृषि विज्ञान केंद्र के कर्मी आंदोलन की राह पर हैं। केवीके कर्मियों को वेतन के साथ मिलने वाले सभी मान्य जीवन यापन के लिए जरूरी भत्के, अवकाश नगदीकरण, ग्रेच्युटी, चिकित्सा हितलाभ सहित उनके अवकाश की उम्र में भी भारी कटौती कर दी गई है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के इस तुगलकी फरमान के बाद कृषि विज्ञान केंद्र के कर्मियों पर एक बहुत बड़ा वज्रपात हुआ है।

कृषि विज्ञान केंद्र के कर्मिज्यों को अपना पूरा भविष्य अंधकारमय नजर आ रहा है। इतना ही नहीं इस आदेश के परिपालन के चलते हुये पूरे देश के कृषि विज्ञान केंद्रों में पिछले कई महीनों से वेतन तक नहीं मिला है। हालत यह हैं कि केवीके कर्मियों के सामने अपने परिवार के पालन पोषण से लेकर जीवन के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक मूलभूत सुविधाएं जुटाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। अगर हालात यही बने रहे तो आने वाले कुछ महीनों में कृषि विज्ञान केंद्र के कर्मियों की हालत बद से बदतर होने से नहीं रोकी जा सकेगी।

यहां यह बताना बहुत जरूरी है कि आखिर कृषि विज्ञान केंद्र हैं क्या और इन्हें खोले जाने की जरूरत क्यों पड़ी। देश में कृषि एवं कृषि से संबंधित विषयों पर अनुसंधान एवं शिक्षा प्रदान करने वाली सर्वोच्च संस्था भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जोकि पूसा, नई दिल्ली में स्थित है के अधीन सम्पूर्ण देश में विभिन्न अनुसंधान संस्थान कार्य कर रहे हैं। इन संस्थानों में होने वाले अनुसंधान को सीधे किसानों के खेत तक पहुंचाने एवं गांव-किसान तक प्रचार-प्रसार के लिए वर्ष 1974 में श्री मनमोहन सिंह मेहता की अध्यक्षता में आई रिपोर्ट के बाद पहला कृषि विज्ञान केंद्र पांडिचेरी में खोला गया था। प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में लगातार कृषि विज्ञान केंद्रों के खोले जाने का सिलसिला जारी है। पूरे देश में लगभग 731 से अधिक कृषि विज्ञान केंद्र कार्य कर रहे हैं।

कृषि तकनीकी के प्रचार-प्रसार एवं किसानों के खेत पर अनुसंधान की सत्यता की जांच और शोध करने के लिए कृषि विज्ञान केंद्रों की भूमिका हमेशा से अग्रणी रही है। जब से कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा संपूर्ण जिले में तकनीकी के प्रचार-प्रसार का कार्य किया जा रहा है, उसके बाद से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एवं कृषि विश्वविद्यालय से निकलने वाले शोध को सीधे किसानों तक पहुंचापाना सर्व-सुलभ हुआ है। इसका परिणाम यह हुआ है कि नवीनतम तकनीकी को प्राप्त करने के बाद हमारा सर्वदाता किसान खाद्यान्न, फल, फूल, सब्जी, दूध, मांस, मछली, तिलहन, दलहन आदि सभी की उपलब्धता सुनिश्चित करके आज देश की 140 करोड़ से अधिक की जनसंख्या को इनकी आपूर्ति के माध्यम से किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होने दे रहा है।

यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा अपितु यह पूर्णता: सत्य है कि पूरी दुनियां में कृषि एवं कृषि से जुड़े विषयों की वैज्ञानिक नवीनतम तकनीकी ज्ञान के प्रचार-प्रसार की इससे बड़ी कोई दूसरी संस्था अभी तक नहीं है। कृषि तकनीकी के प्रचार प्रसार और सीधे आम किसानों तक पहुंच रखने वाली दुनियां की सबसे बड़ी संस्था कृषि विज्ञान केंद्र आज अपने अस्तित्व को बचाए रखने के संकट से जूझ रहे हैं। इनका आगे क्या होगा यह भविष्य के गतज़ में छुपा है। लेकिन वर्तमान में केवीके कर्मियों पर आए संकट से पार पाना उनके लिए मुश्किल हो गया है।

देश में संचालित कृषि विज्ञान केंद्र अलग-अलग संगठनात्मक ढांचे के तहत कार्य कर रहे हैं। सवाज़धिक संख्या में कृषि विज्ञान केंद्र राज्य सरकारों के अधीन संचालित कृषि विश्वविद्यालयों के तहत: आते हैं। इसके बाद काफी संख्या में कृषि विज्ञान केंद्र गैर सरकारी संगठन (एनजीओ), राज्य सरकारें एवं स्वयं आईसीएआर संचालित कर रहे हैं। कृषि विज्ञान केंद्रों को अनुदान देने एवं तकनीकी, रिपोर्टिंज़ आदि कार्यों पर नियंत्रण भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का रहा है। जबकि इन केंद्रों पर प्रशासनिक नियंत्रण एवं नियुक्ति का अधिकार मेजबान संस्थान का है। बताया जा रहा है कि कृषि विज्ञान केंद्र अभी तक प्रोजेक्ट मोड में ही चल रहे हैं।

इसी प्रक्रिया के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एवं मेजबान संस्थान जैसे- कृषि विश्वविद्यालय, एनजीओ आदि के बीच में एक समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) साइन हुआ है। इस एम.ओ.यू. में क्या नियम और शर्तें तय: हुई है, इस बात की जानकारी इन दोनों संस्थाओं के बीच में ही हैं। नियुक्ति के लिए विश्वविद्यालयों द्वारा जारी विज्ञापनों में इस एमओयू के नियम और शर्तों के बारे में कोई पूर्व जानकारी नहीं बताई गई। इतना ही नहीं नियोक्ता द्वारा जारी नियुक्ति पत्रों में भी इन नियम और शर्तों का कोई उल्लेख नहीं है। लेकिन अब विगत कुछ माहों पूर्व भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की तरफसे आए एक तथा कथित पत्र के द्वारा एम.ओ.यू. के अनुसार नियम एवं शर्तों का हवाला देकर कृषि विज्ञान केंद्र पर कार्यरत कर्मियों के मान्य भक्तों में कटौती, अवकाश नगदीकरण, ग्रेच्युटी, अवकाश ग्रहण की अवधि आदि में कटौती करने की बात की जा रही है।

अभी तक कृषि विज्ञान केंद्रों के वेतन भक्तों से लेकर अन्य मदों में शत प्रतिशत अनुदान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा दिया जा रहा था। लेकिन विगत वित्तीय वर्ष में कुछ कटौतियों के बाद से इस वित्तीय वर्ष 2024-25 में इनको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का कहना है कि वह सिर्फ बेसिक, डीए और आवास भत्ता देने के लिए ही बाध्य हैं। बाकी अन्य भत्ते एनपीएस, अवकाश नगदीकरण, ग्रेच्युटी, चिकित्सा भत्ता आदि देने की जवाबदारी मेजबान संस्थान की है। जबकि गौरतलब तथ्य यह है कि देशभर में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा संचालित स्वयं के कृषि विज्ञान केंद्रों में कायरज़ करने वाले कमिज़्यों को संपूर्ण वेतन भक्तों सहित एनपीएस एवं अवकाश बाद के सभी लाभ दिए जा रहे हैं। इतना ही नहीं उन्हें अवकाश प्राप्त करने की अवधि भी आईसीएआर के अनुसार ही दी जा रही है।

इस रस्साकसी के चलते सबसे ज्यादा परेशानी देश में कृषि विश्वविद्यालय के अधीन संचालित कृषि विज्ञान केंद्रों में पैदा हो रही है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा इन सभी मदों में बजट काट दिया गया है। विश्वविद्यालयों द्वारा कोई अतिरिक्त बजट इस हेतु आवंटित नहीं किया जा रहा है। इस कारण कृषि विज्ञान केंद्रों पर वेतन, भक्तों के मद में काफी कम बजट मिल पा रहा है। इसके चलते केवीके कर्मियों को सुचारू वेतन के लाले पड़ रहे हैं। कई राज्यों में कृषि विज्ञान केंद्र के कर्मिज्यों की यह लड़ाई माननीय न्यायालय तक भी पहुंच गई है। माननीय जबलपुर हाईकोर्ट द्वारा इस पर मध्य-प्रदेश के दोनों कृषि विश्वविद्यालयों के केवीके कर्मियों के पक्ष में स्टे ऑर्डर भी दिया जा चुका है।

विदित हो कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा जारी पत्रों क्रमश: 26 मई 1997 एवं 2 सितंबर 1997 के माध्यम से अचानक कृषि विज्ञान केंद्रों के वित्तीय प्रावधानों में बदलाव करके उनको मिलने वाली ग्रांट को मैचिंग शेयर में बदल दिया गया था। जिसमें संपूर्ण ग्रांट की आधी राशि आईसीएआर तथा आधी राशि मेजबान संस्थान को देनी थी। लेकिन जब इस मुद्दे ने राष्ट्रीय स्तर पर तूल पकड़ा और सरकार पर उनके सहयोगियों द्वारा ही दबाव बनाया गया और गैर सरकारी संगठनों के कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर कर दी गई। परिणाम स्वरूप योजना आयोग द्वारा इस पर संज्ञान लेते हुए मार्च 1998 से पुन: देश के सभी कृषि विज्ञान केंद्रों को मिलने वाली वित्तीय सहायता शत प्रतिशत कर दी गई थी।

आज जब केंद्र एवं राज्य सरकारों की प्राथमिकता के केंद्र बिंदु में किसान एवं कृषि है। कृषि और किसान का कल्याण बिना नवीनतम वैज्ञानिक तकनीकी ज्ञान के हो पाना संभव नहीं है। इसलिए भारत सरकार को कृषि विज्ञान केंद्रों के तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए कार्य करने की जरूरत है। कृषि विज्ञान केंद्रों का तंत्र तब तक सुदृढ़ नहीं हो सकता जब तक कि उनमें काम करने वाले वैज्ञानिक एवं कर्मचारी के हितों की रक्षा नहीं की जाती है।

शोध: पॉलिश से घट जाती है मोटे अनाजों की पौष्टिकता

भारतीय वैज्ञानिकों ने अपने नए अध्ययन में खुलासा किया है कि बाहरी परत हटाने और पॉलिश करने से मिलेट (मोटे अनाज) की पौष्टिकता घट जाती है।

यह सही है कि बाहरी परत हटाने से मिलेट के दाने जल्दी पक जाते हैं और लंबे समय तक ताजा बने रहते हैं, लेकिन इसके साथ ही पॉलिश किए मिलेट के यह दाने अपना पोषण भी खो देते हैं।

रिसर्च से पता चला है कि पॉलिश किए मिलेट में भूसी युक्त दानों की तुलना में पोषक तत्व और फाइबर कम होते हैं, जबकि दूसरी तरफइनमें स्टार्च अधिक होता है। इसकी वजह से भारतीय आहार में शर्करा का स्तर (ग्लाइसेमिक लोड) बढ़ सकता है।

बता दें कि अनाज के इन दानों पर एक कठोर बाहरी परत होती है, जिसे दानों को साफ करते समय निकाल दिया जाता है। इसके बाद उसमें से चोकर को अलग कर पॉलिश कर दिया जाता है, जिससे अनाज चमकदार और सुन्दर दिखने लगता है।

यह जानकारी चेन्नई स्थित मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन और हैदराबाद स्थित आईसीएआर-भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान के शोधकर्ताओं द्वारा किए एक नए अध्ययन में सामने आई है। अध्ययन के नतीजे स्प्रिंगर लिंक जर्नल डिस्कवर फूड में प्रकाशित हुए हैं। मोटे अनाज पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, हालांकि इसके बावजूद इनका गेहूं, चावल जैसे दूसरे अनाजों की तुलना में कम ही उपयोग किया जाता है।

अध्ययन में शोधकर्ताओं ने जिन पांच छोटे बीजों वाले भारतीय मिलेट का अध्ययन किया है उनमें कंगनी, सावा या कुटकी, कोदो, सांवा और चेना या पुनर्वा (प्रोसो मिलेट) शामिल हैं। इस अध्ययन का उद्देश्य यह जांचना था कि बाहरी परतों को हटाने से अनाज के पोषण, पकाने और उसके सूक्ष्म संरचनात्मक गुणों पर क्या प्रभाव पड़ता है। गौरलतब है कि सोरगम, बाजरा, ज्वार, रागी, फोनियो, कोदो, कुटकी जैसे मोटे अनाज जिन्हें 'कदन्न' भी कहते हैं, अपने अनेकों गुणों के बावजूद वर्षों से उपेक्षित रहे हैं। इनमें मौजूद पोषक तत्वों की भरमार के चलते इन्हें 'पोषक-अनाज' भी कहा जाता है।

अपने शोध में मिलेट का अध्ययन करने के लिए शोधकर्ताओं ने फूरियर ट्रांसफॉर्म इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रा, एक्स-रे डिफ्रेक्शन और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जैसे विशेष तकनीकों की मदद ली है।

भूसी युक्त अनाज में बरकरार रहते हैं पोषक तत्व इन्हें चमकाने यानी पॉलिशिंग से इसमें से फाइबर, वसा, खनिज और फाइटेट्स निकल जाते हैं, जबकि कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च बढ़ जाता है। अध्ययन में यह भी सामने आया है कि इसकी वजह से सांवा और कुटकी को छोड़कर अन्य सभी तरह के मिलेट्स में प्रोटीन का स्तर भी घट गया। सोरगम, बाजरा, ज्वार, रागी, फोनियो, कोदो, कुटकी जैसे मोटे अनाज जिन्हें 'कदन्न' भी कहते हैं, अपने अनेकों गुणों के बावजूद वर्षों से उपेक्षित रहे हैं।

हालांकि अनाज की बाहरी सख्त परत, जिसे भूसी कहा जाता है उसे हटा देने से अनाज को पकाना और खाना आसान हो जाता है, लेकिन इसकी वजह से इसमें पोषक तत्व और फाइबर कम हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ भूसी युक्त अनाज को पकाने में तो अधिक समय लगा, लेकिन उनके पोषक तत्व बरकरार रहे। इ

सी तरह पॉलिश यानी बिना चोकर वाले मिलेट ने खाना पकाने के दौरान अधिक ठोस पदार्थ खो दिए। साथ ही इन्होने अधिक पानी भी सोख लिया, क्योंकि बीज का बाहरी आवरण हटाने से वो संरचनात्मक रूप से कमजोर हो गए थे। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से पता चला है कि पॉलिशिंग से बीज का आवरण और अनाज की बाहरी परतें हट गई। इसके साथ ही आंतरिक कोशिका परत भी आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गई। फूरियर ट्रांसफॉर्म इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रा और एक्स-रे डिफ्रेक्शन परीक्षणों से पता चला है कि इसकी वजह से अनाज की रासायनिक संरचना में बदलाव आ गया और उनकी कठोरता में कमी आ गई।

शोधकर्ताओं के मुताबिक मिलेट को उसके प्राकृतिक या बेहद कम प्रोसेस करके ही खाना सबसे अच्छा होता है।

रिसर्च: सदी के अंत तक विलुप्त हो जाएंगी एक तिहाई प्रजातियां

वैज्ञानिकों ने आगाह किया है कि यदि ग्रीनहाउस गैसों के बढ़ते उत्सर्जन पर लगाम न लगाई गई तो सदी के अंत तक मौजूदा एक तिहाई प्रजातियां धरती से विलुप्त हो सकती हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कनेक्टिकट से जुड़े जीवविज्ञानी मार्क सी अर्बन द्वारा किए इस अध्ययन के नतीजे अंतराष्ट्रीय जर्नल साइंस में प्रकाशित हुए हैं। अपने इस अध्ययन में उन्होंने पिछले तीन दशकों में प्रकाशित 485 अध्ययनों का विश्लेषण किया है। इसमें बताया गया है कि कैसे प्रजातियां जलवायु में आते बदलावों के प्रति अनुकूल होती हैं।

रिसर्च से पता चला है कि इन प्रजातियों के विलुप्त होने के लिए हम ही जिम्मेवार हैं। इंसानों की वजह से ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ता उत्सर्जन हवा और महासागरों को गर्म कर रहा है। इसकी वजह से मौसम में अप्रत्याशित बदलाव हो रहे हैं जो आगे भी जारी रहेंगे। इसकी वजह से जहां कुछ जगहों पर बेहद अधिक बारिश होगी। वहीं दूसरी तरफ कुछ क्षेत्र जरूरत से ज्यादा गर्म और शुष्क हो जाएंगे।

इस बात की भी आशंका है कि दुनिया को सूखा, आंधी, तूफान और लू जैसी कई और भी चरम मौसमी घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है। यह घटनाएं पहले से कहीं ज्यादा विनाशकारी हो जाएंगी। वातावरण में आते ये बदलाव दूसरे जीवों और पौधों के लिए जीवन कठिन बना देंगे। यह जीव हम इंसानों की तरह अनुकूलन नहीं कर सकते, ऐसे में आने वाले समय में इनका अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है।

अपने इस अध्ययन में जीवविज्ञानी मार्क सी अर्बन ने 485 अन्य शोधों की समीक्षा की है। इसमें यह समझने का प्रयास किया गया है कि यह प्रजातियां वातावरण और जलवायु में आते बदलावों का सामना कैसे कर सकती हैं। इसमें उनके जलवायु अनुकूलन की क्षमता का भी विश्लेषण किया गया है।

इसकी वजह से जहां कुछ जगहों पर बेहद अधिक बारिश होगी। वहीं दूसरी तरफ कुछ क्षेत्र जरूरत से ज्यादा गर्म और शुष्क हो जाएंगे।

इस बात की भी आशंका है कि दुनिया को सूखा, आंधी, तूफान और लू जैसी कई और भी चरम मौसमी घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है। यह घटनाएं पहले से कहीं ज्यादा विनाशकारी हो जाएंगी। वातावरण में आते ये बदलाव दूसरे जीवों और पौधों के लिए जीवन कठिन बना देंगे। यह जीव हम इंसानों की तरह अनुकूलन नहीं कर सकते, ऐसे में आने वाले समय में इनका अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है।

अपने इस अध्ययन में जीवविज्ञानी मार्क सी अर्बन ने 485 अन्य शोधों की समीक्षा की है। इसमें यह समझने का प्रयास किया गया है कि यह प्रजातियां वातावरण और जलवायु में आते बदलावों का सामना कैसे कर सकती हैं। इसमें उनके जलवायु अनुकूलन की क्षमता का भी विश्लेषण किया गया है।

इसकी वजह से जहां छोटे जीव के विलुप्त होने के साथ उसपर निर्भर दूसरे बड़े जीव भी विलुप्त हो सकते हैं। नतीजन इसकी वजह से उभयचर और कुछ दूसरे जीव कहीं अधिक जोखिम का सामना करने को मजबूर होंगे।

आगामी 26 जनवरी तक ग्राम पंचायतों में आयोजित किया जाएगा मुख्यमंत्री जनकल्याण अभियान, सीएम बोले

मुख्यमंत्री ने वीसी से उज्जैन दक्षिण विधान सभा की ग्राम पंचायतों के सरपंचों से चर्चा की

ग्राम पंचायतों को क्रियाशील बनाया जाए, विवाद रहित ग्राम पंचायतों को पांच-पांच लाख रु. मिलेंगे

भोपाल। जागत गांव हमार

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहां है कि जिन ग्राम पंचायत में कोई विवाद नहीं होगा , जिन ग्राम पंचायत में कोई झगड़ा नहीं होगा , एक ग्राम पंचायतों को पांच - पांच लाख रुपए दिए जाएंगे। इन ग्राम पंचायतों को वृंदावन ग्राम योजना से भी लाभान्वित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव गुरुवार को उज्जैन के एनआईसी कक्ष से वीसी द्वारा उज्जैन दक्षिण विधानसभा की ग्राम पंचायतों के सरपंचों से चर्चा कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ.यादव ने वीसी में कहा कि मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान आगामी 26 जनवरी 2025 तक चलेगा। इसमें शासन की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से ग्रामीण जनों को अवगत कराया जाएगा तथा हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें सभी पंचायतों को क्रियाशील बनाना है- वीसी में उज्जैन कलेक्टर श्री नीरज कुमार सिंह द्वारा बताया गया कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप जिले की 589 ग्राम पंचायतों में निरंतर कैंप लगाए जा रहे हैं। दक्षिण विधान सभा की सभी पंचायतों में वीडियो कॉन्फ्रेंस की सुविधा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के द्वारा लैकोड़ा ग्राम पंचायत, तालोद ग्राम पंचायत के सरपंच से चर्चा की गई। बताया गया कि तालोद में फतेहाबाद तक की सड़क का निर्माण हो चुका है। मुख्यमंत्री ने वीसी में कहा कि सरपंच , ग्राम पंचायतों में निरंतर भ्रमण करें। हितग्राहियों से चर्चा करें और उनकी समस्याओं को सुनकर , समय सीमा में उनका समाधान करें। वीसी में जानकारी दी गई की ग्राम पंचायतों में सीसीटीवी

कैमरे लगाए जाने का कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। मुख्यमंत्री ने ग्राम टंकारियापंथ के सरपंच और पटवारी से चर्चा की। ग्राम पंचायत उमरिया खालसा में जैन मुनियों के लिए अतिथि कक्ष भी बनवा दिया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सभी ग्राम पंचायतों में अतिथि कक्ष बनवाया जाए। वर्तमान में जो वेब सीरीज बनाई जा रही है उनमें उज्जैन की ग्राम पंचायतों में भी शूटिंग के लिए की जाए। ग्राम पंचायत करोहन के सरपंच से चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचकोशी यात्रा मार्ग में आने वाली सभी ग्राम पंचायतों को पंचकोशी राशि दिलवाई जाए। मुख्यमंत्री ने वीसी में कहा की सभी पटवारियों को याद रहना चाहिए कि उनके पटवारी हल्के की ग्राम पंचायतों में बंजर भूमि, रकबे की जमीन, आबादी की जमीन कितनी है? उन्होंने निर्देशित किया कि ग्राम पंचायत में स्थित शासकीय जमीन का रिकॉर्ड निकाला जाए तथा वहां भविष्य को ध्यान में रखते हुए क्या विकास के कार्य किया जा सकते हैं इस पर परियोजनाएं बनाई जाएं। सभी ग्राम पंचायतों में बेरोजगार पुरुष और महिलाओं की सूची बनाई जाए। कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने अनपढ़ हैं, वहां पर थानों की क्या स्थिति है, इसकी जानकारी अप-टू-डेट रखी जाए।

ग्राम पंचायतों में सामूहिक विवाह के आयोजन कराए जाएं

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने उन्नत किसानों की जानकारी, महिला पुरुष की शिक्षा, रोजगार संबंध, मेरिट मे आये बच्चों की जानकारी, अस्पताल, स्कूल, जमीन का रकबा, फसलों के सम्बन्धी भी जानकारी भी अपडेट रखने को कहा। मुख्यमंत्री ने वीसी में निर्देश दिए की ग्राम पंचायतों में सामूहिक विवाह के आयोजन कराए जाएं। आगामी वसंत पंचमी पर भव्य स्तर पर सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाए। लोगों को जागरूक किया जाए कि वे शादी और मृत्यु भोज पर अनावश्यक रुपया बर्बाद ना करें, बल्कि इनका उपयोग अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई में करें। मुख्यमंत्री के द्वारा ग्राम पंचायत पंथपिपलाई, खेमासा के सरपंचों से चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में किसी भी तरह की कोई समस्या स्थानीय नागरिकों को नहीं आनी चाहिए। वीसी में जानकारी दी गई की असलाना ग्राम पंचायत में बिजली के तार टूट रहे हैं, इस पर मुख्यमंत्री ने तुरंत इनकी मरम्मत करवाए जाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रशासनिक संकुल भवन में 1 वर्ष की उपलब्धि पर आधारित जनसंपर्क विभाग की प्रदर्शनी का अवलोकन किया और प्रदर्शनी की प्रशंसा की।

पशुपालन विभाग की मंत्री ने की समीक्षा

किसान की आय दोगुना करने में पशुपालन गतिविधियों का विशेष योगदान : पटेल

भोपाल। जागत गांव हमार

पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) लखन पटेल ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में देश और प्रदेश में किसानों की आय दोगुनी करने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। किसान की आय दोगुना करने में पशुपालन गतिविधियों का विशेष योगदान है। मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना सहित अन्य विभागीय योजनाओं में पशुपालन गतिविधियों में किसानों को लगभग 50 फीसदी अनुदान विभाग द्वारा दिया जाता है। विभागीय अधिकारी किसानों को पशुपालन के लिए प्रेरित करें और उनको शासन की योजनाओं का पूरा लाभ दें। मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान के दौरान पशुपालन शिविर लगाया जाए और पशुपालन योजनाओं के अधिक से अधिक प्रकरण स्वीकृत किए जाएं। पशुपालन राज्य मंत्री पटेल ने पशुपालन संचालनालय के सभागार में विभाग की प्रदेश स्तरीय समीक्षा बैठक ली। बैठक में प्रमुख सचिव पशुपालन उमाकांत उमराव, संचालक पशुपालन सहित सभी संभागों के संयुक्त संचालक एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

प्रदेश में 406 लाख पशुओं की आबादी

मंत्री पटेल द्वारा संभागवार विभागीय समीक्षा के दौरान निर्देश दिए गए कि विभाग की चलित पशु चिकित्सा वाहनों का समुचित रखरखाव किया जाए। यह योजना अत्यधिक लोकप्रिय हुई है और पशुपालक बड़ी संख्या में अपने पशुओं का इलाज करवा रहे हैं। प्रदेश में 406 लाख पशुओं की आबादी है, प्रति 1 लाख पशु आबादी पर एक वाहन (कॉल सेंटर 1962) संचालित है। मंत्री पटेल ने निर्देश दिए कि राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अंतर्गत पशुपालकों को कुक्कुट पालन, बकरी पालन, शूकर पालन और चरी/चारा उत्पादन के लिए प्रेरित किया जाए। बड़े शहरों में कड़कनाथ विक्रय से पशुपालक किसानों को अच्छा मुनाफा प्राप्त हो सकता है। महिला स्व-सहायता समूह को राष्ट्रीय पशुधन मिशन की गतिविधियों से जोड़ा जाए। योजना अंतर्गत स्व सहायता समूह को कुक्कुट पालन के लिए कई यूनिट प्रदाय की जाए। केंद्र को एक यूनिट में 100 कुक्कुट प्रदाय करने का प्रस्ताव भिजवाया जाए। वर्तमान में एक यूनिट में 40 कुक्कुट प्रदाय किए जाते हैं। मंत्री ने कहा कि पशुपालक किसानों को साइलेज के इस्तेमाल के लिए प्रेरित किया जाए।

आलतू और आवारा पशुओं की टैगिंग अलग-अलग रंग से की जाए

मंत्री पटेल ने कहा कि पालतू और उन्मुक्त विचरण करने वाले पशुओं की पहचान के लिए यह आवश्यक है कि उनकी टैगिंग अलग-अलग रंग से की जाए। मुख्यमंत्री गौ सेवा योजना के अंतर्गत निर्मित गौशालाओं में पशुओं के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए। बड़ी गौशालाओं में गोबर गैस संयंत्र लगाने के प्रयास किए जाएं। प्रमुख सचिव पशुपालन उमराव ने कहा कि अधिकारी पशु बीमा के लंबित प्रकरणों का बीमा अधिकारियों से निरंतर संपर्क कर निराकरण कराएं। यदि संबंधित बीमा कंपनियां बेवजह किसानों के बीमा दावे रोकती हैं तो उपभोक्ता फोरम में प्रकरण दर्ज कराएं। सभी किसानों को पशु बीमा की दावा राशि दिलाए जाना सुनिश्चित करें।

झाबुआ में स्ट्रॉबेरी की खेती से आदिवासी किसानों के जीवन में आई मिठास

भोपाल। जागत गांव हमार

मध्यप्रदेश के झाबुआ जिले में जब पारम्परिक खेती से आगे बढ़ने की बात आई, तो जनजातीय किसानों ने एक नई दिशा में कदम रखा। जिले के प्रगतिशील किसान रमेश परमार और साथी अन्य किसानों ने अपनी हिम्मत, मेहनत और नवाचार से असंभव को संभव बना दिया है। जिले के जनजातीय बहुल क्षेत्र में पहली बार स्ट्रॉबेरी की खेती का प्रयोग शुरू हुआ। परम्परागत रूप से ज्वार, मक्का और अन्य सामान्य फसलों के लिए जाने जाने वाले इस इलाके में अब किसानों ने उद्यानिकी फसलों की ओर रुख किया है। जिले के रामा ब्लॉक के तीन गांवों भुराडाबरा, पालेड़ी और भंवरपिपलिया में आठ किसानों के खेतों में स्ट्रॉबेरी के पौधे लगाए गए।

झाबुआ में, स्ट्रॉबेरी सामान्यत: ठंडे इलाकों की फसल है, को यहां अनुकूलित परिस्थितियों में उगाने का प्रयोग किया गया। महाराष्ट्र के सतारा जिले से 5000 पौधे मंगवाकर हर किसान के खेत में 500 से 1000 पौधे लगाए गए। हर पौधे की कीमत मात्र 7 रुपए थी, लेकिन इसे उगाने की प्रक्रिया ने किसानों को बागवानी की उन्नत और आधुनिक तकनीकों से रूबरू कराया। रोटला गांव के रमेश परमार ने अपने खेत में ड्रिप और मल्चिंग तकनीक का उपयोग कर 1000 स्ट्रॉबेरी पौधे लगाए। वे बताते हैं कि पहले बाजार में इन फलों को देखा था, लेकिन खरीदने की हिम्मत कभी नहीं हुई। अब जब खुद के खेत में उगाए, तो इसका स्वाद भी चखा और इसकी उच्च कीमत का महत्व भी समझा। रमेश ने 8 अक्टूबर 24 को पौधों की बोवनी की थी और केवल तीन महीनों में फलों की पैदावार शुरू हो गई। वर्तमान में बाजार में स्ट्रॉबेरी की कीमत 300 रुपए प्रति किलो है। फिलहाल उन्होंने अपनी पहली फसल घर के सदस्यों और रिश्तेदारों के साथ बांटी है।

समूह की सफलता

रमेश अकेले नहीं हैं। उनके साथ अन्य किसान भंवरपिपलिया के लक्ष्मण, भुराडाबरा के दीवान, और पालेड़ी के हरिराम ने भी अपनी जमीन पर स्ट्रॉबेरी उगाई है। सभी किसानों के पौधों में फल लगने शुरू हो गए हैं। ये किसान अपनी उपज को लोकल हाट-बाजार और हाईवे के किनारे बेचने की योजना बना रहे हैं।

नवाचार और आत्मनिर्भरता का प्रतीक

झाबुआ जिले की यह पहल न केवल कृषि नवाचार का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, बल्कि यह आत्मनिर्भर भारत की ओर एक ठोस कदम भी है। यह झाबुआ जिले के जनजातीय किसानों ने साबित किया है कि सही मार्गदर्शन, तकनीक और मेहनत से किसी भी क्षेत्र में अपार संभावनाएं पैदा की जा सकती हैं।

आर्थिक और सामाजिक बदलाव की ओर बढ़ रहे जनजातीय किसान

स्ट्रॉबेरी की खेती से न केवल इन किसानों की आमदनी बढ़ने की उम्मीद है, बल्कि यह दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनेगी। यह पहल झाबुआ जिले के लिए उद्यानिकी खेती का एक नया अध्याय खोलेगी। झाबुआ के जनजातीय किसान सीमित संसाधनों के बावजूद बड़े बदलाव की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।

केंद्र सरकार गांवों को लगातार आधुनिक तकनीक और इंटरनेट जैसी सुविधाओं से जोड़ने का काम कर रही

लोगों को नहीं लगाने होंगे ब्लॉक-तहसील के चक्कर अब गांवों में ही मिलेंगी 300 से ज्यादा ई-सेवाएं

भोपाल। जागत गांव हमार

केंद्र सरकार गांवों को लगातार आधुनिक तकनीक और इंटरनेट जैसी सुविधाओं से जोड़ने का काम कर रही है, ताकि ग्रामीण इलाकों में लोगों को डिजिटल सेवाएं आसानी से मिल सकें। इन सुविधाओं के लिए गांव में रहने वाले लोगों को अब ब्लॉक, तहसील या जिला मुख्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, जिससे उनके समय और पैसों की बचत होगी। इसी क्रम में सरकार ने प्राथमिक कृषि साख समितियों - पैक्स को कॉमन सर्विस सेंटर की तरह काम करने की अनुमति दी है। इस फैसले के साथ ही ग्रामीणों को 300 से ज्यादा ई-सेवाओं, जैसे- बैंकिंग, बीमा, कृषि सेवाएं, स्वास्थ्य आदि सेवाएं आसानी से अपने गांव या आस-पास के क्षेत्र में मिल जाएंगी।

पैक्स कप्रचारियों को मिल रही ट्रेनिंग- सरकार की ओर से जारी किए गए डेटा के मुताबिक, 21 नवंबर 2024 तक देशभर में 40,214 पैक ?स को कॉमन सर्विस सेंटर सेवाएं देने के लिए सक्षम बनाई जा चुकी हैं। पैक्स के सीएसी तौर पर बदलाव से गांव के लोग अपने गांव या अपनी ग्राम पंचायत में ही शिक्षा, स्वास्थ्य और तमाम सरकारी सेवाओं और योजनाओं आदि का लाभ डिजिटल माध्यम से ले सकेंगे। राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद और ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड पैक्स के कर्मचारियों को ट्रेनिंग देने के ट्रेनिंग प्रोग्राम और कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप आयोजित कर रहे हैं।

कंप्यूटराइजेशन प्रोजेक्ट से होंगे ये फायदे

- पैक्स को कंप्यूटराइज्ड करने के लिए कॉमन अकाउंटिंग सिस्टम और मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम लागू किया जाएगा।
- लोन तेजी से मिलेगा, ट्रांजेक्शन कॉस्ट में कमी आएगी, पैक्स पारदर्शिता के साथ चल सकेगी।
- 25 से ज्यादा आर्थिक गतिविधियों जैसे- लघु, मध्यम और दीर्घकालिक लोन, बिजनेस प्लान, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट आदि को ईआरपी सॉफ्टवेयर के माध्यम से आसान और पारदर्शी बनाया जाएगा।
- राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की ओर से सिस्टम इंटीग्रेटर्स को इस प्रोजेक्ट के लिए जोड़ा गया है। सिस्टम इंटीग्रेटर्स के जरिए राष्ट्रीय स्तर के सॉफ्टवेयर के इंस्टॉलेशन और पैक्स के पुराने डेटा को डिजिटली अपडेट करने में मदद कर रहे हैं।

कम्प्यूटरीकरण से बढ़ेगी डिजिटल साक्षरता

दोनों सगठनों की पहल से पैक्स तो डिजिटल होंगे ही साथ ही गांवों में डिजिटल साक्षरता बढ़ेगी। सरकार पैक्स को कंप्यूटराइज्ड कर इनके वर्क सिस्टम को एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग बेस्ड एक कॉमन नेशनल सॉफ्टवेयर से लिंक कर रही है। इस प्रोजेक्ट के तहत 2516 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जिसमें अब तक 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 67,930 पैक्स के कंप्यूटराइज़ेशन के प्रस्तावों को अनुमति दी गई है।

1.25 लाख किसानों को मिलेंगे सोलर पंप

10 से ज्यादा गाय पालने पर सब्सिडी का लाभ भी किसानों को मिलेगा

भोपाल। जागत गांव हमार

मध्य प्रदेश के किसानों की आर्थिक आय को बढ़ाने से लेकर पशुपालकों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गुरुवार को पत्रकारों से चर्चा में सरकार के रोड मैप की जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को दोगुना किया जाएगा। इसमें अगले चार साल में एक लाख 25 हजार अस्थाई बिजली कनेक्शन वाले किसानों को सोलर पंप दिए जाएंगे। इससे किसान बिजली आपूर्ति में आत्मनिर्भर बनेंगे। साथ ही सीएम मोहन यादव ने कई योजनाओं पर बातें की।

पशुपालकों को मिलेगा सब्सिडी: सीएम मोहन यादव ने कहा कि अगले पांच साल में सिंचाई क्षमता 50 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर एक करोड़ हेक्टेयर की जाएगी। इसके अलावा जो पशुपालकों 10 गायों से अधिक गाय का पालन करेंगे उन्हें सब्सिडी दिया जाएगा। साथ ही जिस तरह गेहूं और धान की खरीद पर किसानों को बोनस दिया जाता है, उसी तर्ज पर दूध पर भी बोनस दिया जाएगा। इससे अधिक से अधिक किसान पशुपालन की तरफ आकर्षित होंगे। राज्य में पशुपालन पर जोर देने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है।

मध्य प्रदेश में शुरू होगा मिशन

इसके अलावा उन्होंने कहा कि प्रदेश में चार मिशन युवा, महिला, किसान और गरीब कल्याण 26 जनवरी से शुरू किए जाएंगे। सीएम ने कहा कि प्रदेश में वर्तमान में कुल विद्युत उपलब्ध क्षमता 23 हजार 30 मेगावाट है, आगामी 5 वषोंज में कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 31000 मेगावाट करने का लक्ष्य है। सीएम ने कहा कि प्रदेश में महिला स्व सहायता समूह को जन आंदोलन बनाया जाएगा। वर्तमान में 25 लाख महिलाएं स्व सहायता समूहों से जुड़ी हैं, यह संख्या 4 साल में 50 लाख तक बढ़ाई जाएगी।

किसानों के लिए किए गए ये काम

- आयुष्मान भारत का ऑनलाइन निराकरण शुरू किया गया।
- खुले में मांस के बिक्री को प्रतिबंधित किया गया।
- दुग्ध उत्पादन योजना में अब तक 4 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड वितरित कर मप्र देश में सबसे आगे है।
- इंदौर की हुकुमचंद मिल के 4800 मजदूरों की बकाया पैसा 224 करोड़ रुपए का भुगतान करवाया गया।
- रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना में किसानों को 13900 रुपए प्रति हेक्टेयर की अतिरिक्त मदद देने का निर्णय लिया गया।
- सोयाबीन का समर्थन मूल्य 4892 रुपए प्रति क्विंटल की दर से उपार्जन करने का निर्णय लिया गया।

साइबर तहसील के नामांतरण और बंटवारा जैसे राजस्व प्रकरणों बढ़ाने के लिए मप्र सरकार और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बीच एमओयू हुआ।

पूर्णिया के किसान ने नर्सरी में 9 उन्नत किस्मों के परवल को उगाया

अब घर बैठे किसान डाक से मंगवा सकते हैं परवल के उन्नत बीज

भोपाल।

परवल की खेती अब खेत की ही मोहताज नहीं। आप इसे घर के आंगन या बड़े गमले में भी उगा सकते हैं। सबसे खास बात ये कि इसका बीज (कटिंग) लेने के लिए आपको बाजार में या दुकान पर भाग के जाने की जरूरत नहीं होगी बल्कि घर बैठे इसे मंगवा सकते हैं, वह भी डाक से। बिहार में यह नई सुविधा शुरू हुई है। दरअसल, परवल को बिहार की पसंदीदा सब्जी कहते हैं। यह भी माना जाता है कि यहीं से परवल निकल कर देश के अलग-अलग हिस्से में गया है, तो अगर आप इसके उन्नत बीज को घर बैठे मंगवाना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस से यह काम आसानी से हो जाएगा। पूर्णिया के एक किसान ने अपनी नर्सरी में 9 उन्नत किस्मों के परवल को उगाया है। यह किसान देश के अलग-अलग हिस्सों में मांग के हिसाब से इसके बीज (जो लता यानी कटिंग के रूप में होता है) भेज रहा है। अहम बात ये है कि इन उन्नत वैरायटी के परवल और उसके कटिंग को तैयार करने में बिहार कृषि विश्वविद्यालय का बड़ा रोल है। कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक राजभवन वर्मा ने रिसर्च के बाद परवल की 9 नई किस्में तैयार की हैं। ये सभी किस्में पूर्णिया के किसान मायानंद विश्वास की नर्सरी में लगाई गई हैं। इन सभी परवल की कटिंग को देशभर में सप्लाई करने में पूर्वी जोन के पोस्ट मास्टर जनरल मनोज कुमार का बड़ा रोल है। पहले परवल की कटिंग को भेजने के लिए कूरियर का सहारा लिया जाता था जो कि महंगा काम था। अब डाक विभाग यह काम किसानों के लिए सस्ते में कर रहा है, जो लोग परवल की कटिंग की मांग करते हैं, उन्हें डाक के जरिये उन्नत किस्म की कटिंग भेजी जाती है। पूर्णिया के किसान मायानंद विश्वास ने कहा कि उनकी नर्सरी में राजेंद्र 1, राजेंद्र 2, स्वर्ण अलौकिक, स्वर्ण रेखा, बंगाल ज्योति, बंगाल ज्योति 2, डंडारी और दुधयारी समेत 9 वैरायटी के परवल उगाए हैं। इन सभी किस्मों का रंग और स्वाद अलग-अलग है। ऑर्डर मिलने पर भारत के किसी कोने में डाक से इसकी कटिंग भेजी जाती है। 40 पौधे के पैकेट के लिए 2500 रुपए देने होते हैं।

डाक विभाग की पहल

किसान ने बताया कि लोगों की डिमांड पर पूर्णिया से दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा सहित दक्षिण भारत के राज्यों में भी परवल के पौधे (कटिंग या बीज) भेजे जा रहे हैं। इन किस्मों की खास बात ये है कि इसके पौधे जल्द लगते हैं और फल जल्द मिलते हैं। इस काम में डाक विभाग का अहम रोल है क्योंकि उसके अधिकारी किसान मायानंद विश्वास को बता चुके हैं कि परवल के पौधे की पैकेजिंग कैसे करें ताकि अधिक दिनों तक वह सुरक्षित और ताजा रहे।

मैनेजर ने किराए की जमीन पर उगाई अंबाड़ी भाजी

नाइजीरिया से मंगवाए बीज, 800 से 1200 रुपए प्रति किलो में बिक्री

मनावर। जागत गांव हमार

अगर आपको कुछ करना है, तो खुद के संसाधन जरूरी नहीं। यह साबित किया है धार जिले के मनावर के किसान ने। अपनी मेहनत और लगन से किराए की जमीन पर न सिर्फ फसल उगाई, बल्कि मोटा मुनाफा भी कमा रहे हैं। ये हैं पवन कुशवाह। पेशे से निजी कंपनी में मैनेजर। जागत गांव हमार अपने इस अंक में इस बार मूलतः बाकानेर गांव के रहने वाले पवन कुशवाह (48) से मिलवाते हैं। बीकॉम तक पढ़ाई की है। उन्होंने बताया कि कैसे दो बीघा जमीन पर अंबाड़ी भाजी की खेती शुरू की। इसकी मदद से सालाना करीब तीन लाख रुपए से ज्यादा का प्रॉफिट कमा रहे हैं। यही नहीं, अन्य किसानों को भी विलुप्त हो रही इस फसल को उगाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। किसानों को प्रोत्साहित करने और उत्पादन बढ़ाने के लिए इसके बीज निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं।

पुरानी परंपरा को कायम रखने के लिए उगाई फसल

किसान पवन कुशवाह बताते हैं, पिछले कई साल से किसानों के साथ जैविक और टिकाऊ खेती के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूं। खेती के साथ अंबाड़ी भाजी खाने का शौक है। मार्केट में यह आसानी से मिलती नहीं है। यूं कहें कि यह विलुप्त होती जा रही है। कई बार खेती करने के बारे में सोचा, लेकिन खुद की जमीन नहीं होने से पीछे हट जाता था। इसके बाद आइडिया आया कि किराए से भी जमीन ली जा सकती है। जहां काम करता हूं, उनके पास दो बीघा जमीन है। करीब तीन साल पहले मालिक से बात की, तो वह तैयार हो गए। सालभर के करीब 10 हजार रुपए उन्हें किराए के रूप में दे देता हूं। उन्हें भी सब्जी मिल जाती है।

नाइजीरिया से ऑनलाइन अंबाड़ी भाजी के बीज मंगवाए। कारण- यहां के बीज की क्वालिटी ज्यादा अच्छी होती है। इससे उत्पादन भी ज्यादा होता है। जैविक तरीके से अंबाड़ी भाजी की खेती शुरू कर दी। बाद में हल्दी और सौंफ का भी उत्पादन करने लगे। तीन से चार लोग काम पर रखे। शुरुआती साल में अंबाड़ी की भाजी तैयार कर स्थानीय स्तर पर बेची। निमाड़ क्षेत्र में कुछ विशिष्ट (विवाहोत्सव में मंडप के दिन, दिवाली की पड़वा तिथि) पर अनिवार्य रूप से अंबाड़ी भाजी बनाकर परंपरा निभाया जा रहा है। ऐसे शौकीन लोगों तक भाजी पहुंचाने और परंपरा कायम रखने के लिए इसकी फसल उत्पादन करने का फैसला लिया है।

गौमूत्र के छिड़काव से कीटों से बचाव

पवन के मुताबिक अंबाड़ी की बुवाई सामान्यतः बारिश के मौसम में की जाती है। प्रति बीघा 750 ग्राम बीजों की आवश्यकता होती है। दो पौधों की बीच की दूरी करीब एक फीट रखनी होती है, जबकि दूसरी कतार की दूरी करीब दो से ढाई फीट रखनी होती है, जिससे पौधे को फैलने के लिए जगह मिले। बीज की कीमत 200-300/-किलो होती है। जैविक पद्धति से उत्पादन करने पर एक बार गोबर खाद दिया जाता है। कीट नियंत्रण के लिए गौमूत्र का छिड़काव किया जाता है। इसकी खेती करने में खास तैयारियों की जरूरत नहीं पड़ती है।

800-1200 रुपए प्रति किलो बिकती है

पवन बताते हैं, 'सामान्य तरीके से निराई-गुड़ाई के बाद अक्टूबर महीने में इसके फूल आना शुरू हो जाते हैं। फूल खिलने के बाद इसके पत्ते तोड़े जाते हैं। 20 किलो हरी पत्ती को पारंपरिक तरीके से भाजी बनाकर सुखाने पर दो से तीन किलो सूखी भाजी मिलती है। बाजार में इसकी कीमत 800-1200 रुपए किलो तक मिलती है। वहीं, एक बीघा से तकरीबन 1 से 1.5 क्विंटल सूखी भाजी मिलती है। सूखी भाजी बनाने में बड़ा खर्च मजदूरों का रहता है, क्योंकि भाजी बनाने में पारंपरिक तरीके का पालन करना पड़ता है। औसतन मजदूर का खर्च 30 हजार रुपए आता है।

सोशल मीडिया पोस्ट से मिली पहचान

पवन बताते हैं कि पिछले साल यानी 2023 में 50 किलो अंबाड़ी की भाजी तैयार करके रखी थी। इसे बेचने के लिए कई लोगों से संपर्क करना था। मैं सोशल मीडिया पर इंदौर के सोशल ग्रुप 'इंदौर वाले' पर जुड़ा था। एक दिन बैठे-बैठे अंबाड़ी की भाजी की पोस्ट शेयर कर दी। दो-तीन दिन में 100 से अधिक लोगों ने बुकिंग कर ली। महज एक हफ्ते में स्टॉक खत्म हो गया। कई ग्राहकों को समय पर उपलब्ध भी कर नहीं पाए। इस पोस्ट के माध्यम से स्थानीय ग्राहकों के अलावा इंदौर, खंडवा, धार, खरगोन, बड़वानी, झाबुआ से लेकर राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और गुजरात के कस्टमर भी जुड़ गए। वहीं, कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं, जिन्होंने विदेश में बसे अपने रिश्तेदारों और परिचितों के लिए विशेष रूप से मांग की।

देखने में केसर की तरह लगती है...

पवन कुशवाह बताते हैं, सर्दियों की शुरुआत होते ही अंबाड़ी के पत्ते तोड़कर पहले दिन छांव में सुखाए जाते हैं। दूसरे दिन पत्ते नरम होने के बाद लकड़ी की मोगरी से कूटा जाता है। फिर इन पत्तियों को लाल पत्थर की फर्सी पर रोला जाता है। इनको तब तक रोला जाता है, जब तक कि रस पत्ती को तरबतर न कर दे। इसके बाद इनकी लटें बनाकर अलग-अलग किया जाता है। कुछ घंटे छांव में सुखाने के बाद एक बार फिर इन लटों को हाथों से रोला जाता है। तीसरे दिन इन लटों को धूप में सुखाया जाता है। फिर इसे आधा किलो और एक किलो के बॉक्स में पैक कर ग्राहकों को कुरियर के जरिए भेजा जाता है। एक किलो की पैकिंग और डिस्पैचिंग का खर्च 200 रुपए आता है। यह केसर की तरह दिखती है।

ऐसी होती है अंबाड़ी की भाजी

अंबाड़ी मूलतः अफ्रीका की मूल प्रजाति कही जाती है। वहां की वैरायटी के फूल इन दोनों भारतीय प्रजाति से भिन्न गहरे महरून रंग के होते हैं। इनमें ज्यादा खटास होती है। पवन ने अपने मित्र के माध्यम से नाइजीरिया से लाल अंबाड़ी का बीज बुलवाकर उत्पादन किया है, जो जैविक तरीके से किया जाता है।

महाराष्ट्र, तमिलनाडु में होती है खेती

अंबाड़ी की खेती देश के अलग-अलग हिस्सों में की जाती है। मराठी में अंबाड़ी, तेलुगु में गोनगुरा, मलयालम में इसे कंजूर कहा जाता है। अंबाड़ी की भारत में दो तरह की प्रजाति है- हरी और लाल अंबाड़ी। लाल अंबाड़ी में हरी अंबाड़ी की तुलना में ज्यादा खट्टापन होता है।

ट्रांसपोर्ट में समस्याओं के कारण बहुत सारा खाना बर्बाद

देश में फल और सब्जियों की उपलब्धता बढ़ी, लेकिन चुनौतियां अभी भी बरकरार

देश में पिछले 10 सालों में फल और सब्जियों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में 7 किलो और 12 किलो की बढ़ोतरी

नई दिल्ली/भोपाल। जागत गांव हमार

पिछले 10 सालों में मप्र समेत देश के ई राज्यों फल और सब्जियों की उपलब्धता में बढ़ोतरी हुई है। स्टेट बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार, देश में पिछले 10 सालों में प्रति व्यक्ति आय में सब्जियों में क्रमश: 12 किलो और 7 किलो का इजाफा हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार, देश के कई राज्यों में फल और सब्जियों के उत्पादन में बढ़ोतरी देखी गई है, जिनमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब और जम्मू कश्मीर जैसे राज्य शामिल हैं। लेकिन वहीं, कई उत्तर-पूर्वी राज्यों में प्रति व्यक्ति उत्पादन में गिरावट आई है।

पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट की कमी- देश में प्रति व्यक्ति 227 किलो के करीब फल और सब्जियां का उत्पादन हो रहा है, जो कि पहले से तय 146 किलो से अधिक है। फिर भी 30-35 प्रतिशत फल और सब्जियां नष्ट हो जाती हैं। देश में स्टोर और पैकेजिंग की कमी और ट्रांसपोर्ट में समस्याओं के कारण बहुत सारा खाना बर्बाद हो जाता है, जिसका असर खपत पर भी पड़ता है।

मौसम की मार झेल रहे किसान

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अत्यधिक गर्मी और सर्दी की लहरों के कारण कृषि उत्पादन में गिरावट आई है। विशेष रूप से गेहूं की पैदावार पर तापमान बढ़ने से नकारात्मक असर पड़ा है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार, तापमान 30 डिग्री से ऊपर बढ़ने पर गेहूं की पैदावार में 3-4 प्रतिशत की कमी हो सकती है।

महंगाई में थोड़ी राहत

देश में फल और सब्जियों के दामों में आई कमी के कारण खुदरा महंगाई घटकर 5.48 प्रतिशत पर आ गई है, जबकि पिछले महीने यह 6 प्रतिशत से अधिक थी। अक्टूबर में 42.2 प्रतिशत वृद्धि के बाद, नवंबर में यह गिरकर 29.3 प्रतिशत हो गई। हालांकि, इस दौरान प्रोटीन महंगाई में वृद्धि देखने को मिली है।

राज्यों के बीच महंगाई में अंतर

रिपोर्ट के अनुसार, मध्यम और हाई इनकम वाले राज्यों में खाद्य महंगाई कम हुई है, जबकि निम्न आय वाले राज्यों में महंगाई ज्यादा है। इसका कारण श्रमिकों का उच्च आय वाले राज्यों में जा रहें है, जिससे बाद के राज्यों में महंगाई कम हो रही है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि गैर-कृषि श्रमिकों के वेतन में वृद्धि का खाद्य महंगाई पर कोई खास असर नहीं पड़ता।

इथेनॉल उत्पादन ने बदल दी तस्वीर

किसानों की इनकम में चौका लगाएगा मक्का

भोपाल। जागत गांव हमार

पिछले एक दशक में मक्के का उत्पादन 25 मिलियन से बढ़कर लगभग 38 मिलियन टन तक पहुंच चुका है, लेकिन अब भी मांग के हिसाब से आपूर्ति नहीं हो पा रही है। इसकी वजह यह है कि मक्का एक इनर्जी क्रॉप के तौर पर उभरा है, जिससे इसका इस्तेमाल इथेनॉल बनाने के लिए, इस्तेमाल हो रहा है। इथेनॉल की पेट्रोल में ब्लेंडिंग करके पेट्रोलियम का आयात कम करने का सरकार का प्लान है। इसलिए मक्के की खेती करना किसानों के लिए लाभ का सौदा साबित होगा। ज्यादातर राज्यों की मंडियों में मक्का अपनी एमएसपी 2225 रुपए प्रति क्विंटल से अधिक कीमत पर बिक रहा है। इथेनॉल के लिए इसका कितना उपयोग हो रहा है इसकी एक तस्वीर आप इन आंकड़ों से देख सकते हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, पिछले वर्ष इथेनॉल बनाने के लिए लगभग 6 मिलियन टन मक्का का उपयोग किया गया है। तेल मार्केटिंग कंपनियों ने एथेनॉल आपूर्ति वर्ष 2024-25 के लिए लगभग 837 करोड़ लीटर एथेनॉल आवंटित किया है। जिसमें मक्का की हिस्सेदारी सबसे अधिक 51.52 प्रतिशत (लगभग 431.1 करोड़ लीटर) की है। इसका मतलब यह है कि सरकार मक्का से इथेनॉल बनाने पर जोर दे रही है। ऐसा करने से इसकी कीमतें बढ़ेंगी और उच्च कीमतों के कारण मक्का की खेती किसानों को अच्छा रिटर्न देगी। इथेनॉल के इस्तेमाल से ही भारत मक्का आयातक भी बन गया है, जिससे विश्व बाजार में हलचल मची हुई है। कुल मिलाकर परिस्थितियां किसानों के पक्ष में हैं। मक्का की खेती में अन्य फसलों के मुकाबले लागत कम है और कम पानी की खपत के कारण यह फसल पर्यावरण के ज्यादा अनुकूल है।

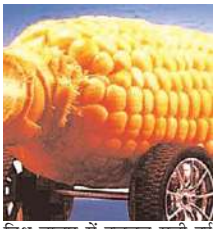

उत्पादन बढ़ाने की पहल

मक्के से इथेनाल बनाने को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार कोशिश कर रही है। इसके तहत ऐसे क्षेत्रों में मक्का की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है जहां इसके लिए अच्छी परिस्थितियां मौजूद हैं फिर भी किसान इसकी खेती नहीं करते थे। इसके लिए केंद्र सरकार ने इथेनॉल उद्योगों के जलग्रहण क्षेत्र में मक्का उत्पादन में वृद्धि नाम से प्रोजेक्ट शुरू किया है। जिसकी जिम्मेदारी आईसीएआर के अधीन आने वाले भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान को दी गई है। इसके तहत मक्का उत्पादन बढ़ाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट पर निदेशक डॉ. एसएस जाट का कहना है कि इथेनॉल के लिए मक्का उत्पादन बढ़ाने की इस मुहिम में एफपीओ, किसान, डिस्टिलरी और बीज उद्योग को साथ लेकर काम किया जा रहा है। किसानों को ज्यादा पैदावार देने वाली किस्मों के बीजों का वितरण किया जा रहा है।

बर्ड फ्लू फ्री अंडे-चिकन बेचना चाहते हैं तो ऐसे मिलेगा सर्टिफिकेट, करने होंगे ये जरूरी काम

भोपाल। पोल्ट्री प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए अंडे-चिकन को बर्ड फ्लू फ्री करने की कोशिश चल रही है। केन्द्र सरकार चाहती है कि अंडे-चिकन का बर्ड फ्लू ही नहीं और भी दूसरी बीमारियों से रहित प्रोडक्शन हो। इसके लिए डिजीज फ्री कंटेनमेंट जोन बनाने की भी तैयारी चल रही है। लोकल मार्केट में भी डिजीज फ्री अंडे-चिकन की डिमांड होने लगी है। यही वजह है कि अब छोटा हो या बड़ा सभी पोल्ट्री फार्मर को ये बताया जा रहा है कि डिजीज फ्री अंडे-चिकन का प्रोडक्शन कैसे किया जा सकता है। गुरु अंगद देव वेटरनरी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी (गडवासु), लुधियाना के पूर्व वाइस चांसलर का कहना है कि आज क्लाइमेट चेंज के चलते बहुत बदलाव आ चुका है। हम अगर अपने पशु-पक्षी और उनसे मिलने वाले प्रोडक्ट को डिजीज फ्री रखना चाहते हैं तो हमे बॉयो सिक्योरिटी का पालन करना होगा।

जागत गांव हमार, सलाहकार मंडल

1. **प्रो. डा. केआर मौर्य, पूर्व कुलपति,** राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसासमस्तीपुर (बिहार) एवं महात्मा ज्योतिराव फूले विश्वविद्यालय, जयपुर (राजस्थान) ईमेल-kuber.ram@gmail.com, मोबा- 7985680406

2. **प्रो. डा. गैब्रियल लाल, प्रोफेसर,** आनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन विभाग सैम हिंगिन बॉटम यूनिवर्सिटी आफएग्रीकल्चर, टेक्नालोजी एंड साइंसेज, प्रयागराज, उप्र। ईमेल- द्दड्डद्बड्ढiyal.lal @shiats.edu.in, मोबा- 7052657380

3. **डा. वीरेन्द्र कुमार,** प्रोफेसर एंड हेड, पौध रोग विज्ञान विभाग, डा. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय परिसर ढोली, मुजफ्फरपुर बिहार। ईमेल- birendraray@gmail.com मोबा- 8210231304

4. **डा. नरेश चन्द्र गुप्ता, वैज्ञानिक,** मृदा विज्ञान, कृषि महाविद्यालय बिरसा, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, कॉके, रॉची झारखण्ड। ईमेल- ncgupt-abau@gmail.com, मोबा- 8789708210

5. **डा. देवेंद्र पाटिल, वैज्ञानिक** (शस्य विज्ञान) कृषि विज्ञान केन्द्र, सीहोर (मध्यप्रदेश) सेवनिया, इछावर, सिहोर (मप्र) ईमेल- dpatil889@gmail.com, मोबा- 8827176184

6. **डा. आशुतोष कुमार सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर,** एग्री विजनेस मैनेजमेंटकृषि अर्थशास्त्र विभाग, एकेएस,विश्वविद्यालय, सतना, मप्र ईमेल- kumar.ashu777@gmail.com, मोबा- 8840014901

7. **डा. बिनीता सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर** आनुवांशिकी एवं पौध प्रजनन विभाग एकेएस विश्वविद्यालय, सतना, मप्र ईमेल- singhvineeta123@gmail.com, मोबा- 8840028144

8. **डा. आरके शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर,** परिजीवी विज्ञान विभाग, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना, बिहार। ईमेल- drrksharmabvc@gmail.com, मोबा- 9430202793

9. **डा. दीपक कुमार, सहायक प्राध्यापक,** मृदा एवं जल संरक्षण अभियंत्रिकी विभाग, गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पन्तनगर, उत्तराखण्ड। ईमेल- deepak.swce.cot.gbpuat@gmail.com, मोबा- 7817889836

10. **डा. भारती उपाध्याय, विषय वस्तु विशेषज्ञ** (शस्य विज्ञान) कृषि विज्ञान केन्द्र, विरौली, समस्तीपुर, बिहार। ईमेल-bharati.upadhya@rpcau.ac.in, मोबा- 8473947670

11. **रोमा वर्मा,** सब्जी विज्ञान विभाग महात्मा गांधी उद्यानिकी एव् वानिकी विश्वविद्यालय, पाटन, जिला- दुर्ग, छत्तीसगढ़। ईमेल- romaverma35371@gmail.com, मोबा- 6267535371

जागत गांव हमार के सुधि पाठकों...

» जागत गांव हमार कृषि, पंचायत और ग्रामीण विकास आधारित समाचार पत्र है, जिसके लिए आपका स्नेह और प्यार हमें शुरू से मिलता रहा है। हम आशा और विश्वास करते हैं कि आगे भी मिलता रहेगा।

» समाचार पत्र के लिए विशेषज्ञों की राय, प्रकाशन योग्य सामग्री के साथ-साथ आपके समक्ष इसे पहुंचाने तक हमारी जिम्मेदारी बड़ी चुनौतीपूर्ण है। आपके सहयोग से ही हम इस चुनौती का सामना कर पाएंगे।

» ऐसे में हमारी आपसे अपेक्षा और आग्रह है कि जागत गांव हमार के वार्षिक सदस्य बनें और इसके लिए नीचे लिखे गए नंबर पर संपर्क करें।

संपर्क करें- अजय द्विवेदी-9229497393, 94250485889

"आपका सहयोग हमारी मजबूती का आधार बनेगा"

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। संपादक: अजय कुमार द्विवेदी, स्थानीय संपादक: अरविंद मिश्रा, संपर्क -9229497393, 9425048589, ईमेल:- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)